

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस)

अपील संख्या 7/2021

निर्णय दिनांक :- 11.05.2022

लादी देवी पुत्री स्व० नारायण पत्नी रामेश्वर उम्र 59 वर्ष जाति बैरवा निवासी भानपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज० हाल निवासी ग्राम दानी की डांणी, निवासी तामडिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर राज०

-अपीलान्त

बनाम

1. किशना पुत्र हरनाथ तथाकथित दत्तक पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम भानपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर राज०
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज०

-रेस्पोडेन्टस

उपस्थित अधिवक्ता

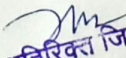
हनुमान सिंहागं अपीलार्थी के अधिवक्ता  
बनवारी लाल शंमा गैर अपीलार्थी के अधिवक्ता

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय तहसीलदार फागी दिनांक 11.01.1983 नामांतरण संख्या 353

निर्णय

अपीलान्त की ओर से हनुमान सिंहाग एडवोकेट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय तहसीलदार फागी दिनांक 11.01.1983 पेश की गई। जिसका संक्षेप सार निम्नुसार है।

यह कि अपीलान्त मृतक स्व० नारायण पुत्र रामनाथ जाति बैरवा, निवासी ग्राम भानपुरा की मृत्यु पर उसकी एक मात्र वारिस उसकी पत्नी श्रीमती ग्यारसी देवी एवं उसकी जाईन्दा पुत्री अपीलान्त लादी देवी है। अपीलान्त कीह पैतृक सम्पत्ति वाके ग्राम भानपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज० में स्थित खाता संख्या 173 के खसरा संख्या 98 कुल किता 1 कुल रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा में अपीलान्त के पिता का 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 174 के खसरा संख्या 98/325 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में हिस्सा 1/4 तथा खाता संख्या 175 के खसरा संख्या 37 रकबा 13 बिस्वा खसरा संख्या 39 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 95/316 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 98/322 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 98/323 रकबा 7 बिस्वा खसरा संख्या 98/324 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 99 रकबा 12 बिस्वा खसरा संख्या 101 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 102 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा संख्या 103 रबा 19 बिस्वा खसरा संख्या 105 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा में हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड था। जिसका नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विधि विरुद्ध तरीके से अपने

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
दूदू

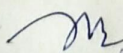
आपको नारायण पुत्र रामनाथ का दत्तक पुत्र बताते हुए खुलवा लिया। जबकि अपीलान्ट के पिता ने अपने जीवनकाल में किसी व्यक्ति को गोद नहीं लिया, ना ही कोई दत्तक ग्रहण किया फिर भी रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने रेवेन्यू अधिकारियों के साज बाज करके अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया। जबकि स्वयं नारायण की एक मात्र जाइन्दा पुत्री अपीलान्ट है। उक्त नामान्तकरण को जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब उसने अपनी माता की मृत्यु दिनांक 25.5.2015 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा प्रमाण पत्र बनवाकर पटवारी हल्का से अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने के लिए मिली तो पटवारी से मिलकर जानकारी की तो पता चला कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा पूर्व से ही अपने नाम लगवा रखा है। अपीलान्ट की माता के नाम आधा हिस्सा है एवं आधा हिस्से का नामान्तकरण रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपने आपको नारायण का दत्तक पुत्र बनवाते हुए खुलवा लिया है। उक्त नामान्तकरण के संपूर्ण रिकार्ड की नकले दिनांक 16.07.2015 को निकलवाने पर अपीलान्ट का उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील अपीलान्ट श्रीमान न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्य के विपरित होने से निरस्तनीय है।

2 यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सहज सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वारिसों की जाँच किये बिना ही मनमाने व विधि विरुद्ध तरीके से अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने में अहम कानूनी भूल की है। चूँकि उक्त नामान्तकरण विरासत का नामान्तकरण था। जिसका ग्राम मुखियत द्वारा स्वीकृत किया जाना आवश्यक था। परन्तु रेस्पोंडेंट संख्या 1 उक्त नामान्तकरण साज बाज तरीके से खुलवाया है। उक्त नामान्तकरण संख्या 353 जो कि अपीलान्ट के पिता के नाम खातेदारी में था। उसको बाद में दिनांक 30.11.1991 को भरवाकर पंचायत में तस्दीक नहीं करवाकर 30.01.1992 को राजस्व अभियान के कम्प मेहन्दवास में खुलवाया है। जो कि अपीलान्ट की पंचायत नहीं होकर दूसरी पंचायत है ताकि उक्त नामान्तकरण का किसी को पता नहीं चल सकें। इसलिए उक्त नामान्तकरण को पंचायत के कोरम में प्रस्तुत नहीं कर तहसीलदार फागी से खुलवाया है इसलिए उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

4 यह कि अपीलान्तीन आदेश को ग्राम पंचायत के समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं किया। क्योंकि उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत की कोरम प्रस्तुत किया जाता है तो सरपंच को मृतक वारिसों की जानकारी स्वयं को रहती है या वह सम्बन्धित वार्ड पंच से भी उक्त पुस्त वंशावली को तस्दीक करवा सकता है। इसलिए अपीलान्ट को हितों से महरूम करने की

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
दूबू

नियत से उक्त नामान्तकरण गैरकानूनी तरीके से राजस्व अभियानों में स्वीकृत कराये जाने से भी काबिले निरस्त योग्य है।

5 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो मृतक के वारिसों की जाँच की है ना ही नारायण के फौत होने के उपरान्त उसके वारिसों की जाँच नहीं कर मात्र इस आधार पर नामान्तकरण तस्दीक कर दिया कि उक्त खाता भूल से रह जाने के कारण नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया जा सका। जबकि उक्त खाता भूल से नहीं रहा बल्कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 नारायण का वारिस ही नहीं है तो उनकी सम्पूर्ण आराजीयात की जानकारी नहीं होने की वजह से उक्त नामान्तकरण खुलने रह गया था। उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर विधि विरुद्ध तरीके से उक्त नामान्तकरण खोला गया है। जिसको खारिज किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है तथा ना ही अपीलान्त को सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया है। इसलिए भी उक्त निर्णय काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि मृतक के वारिसों के उसके विधवा के अलावा उसकी पुत्री की भी थी फिर भी मनमाने तरीके से बिना जांच किये बिना ही रेस्पोंडेन्ट को दस्तक पुत्र मानकर निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

7 यह कि मृतक नारायण ने अपने जीवनकाल में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को कभी गोद नहीं लिया एव ना कभी किसी प्रकार से कोई दस्तावेज गोदनामा/दत्तकनामा उसके हक में निष्पादित किया फिर भी रेस्पोंडेन्ट अपने आपको गोद पुत्र बताते हुए अपीलान्त की पैतृक भूमि को अपने नाम करवा लिया जिसका उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इसलिए उक्त अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्तनीय योग्य है।

8. यह अधीनस्थ न्यायालय ने वर्णित सम्पति अपीलान्त के पिता स्व० नारायण की सम्पति होने एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार नारायण की मृत्यु उपरान्त उसकी प्रथम श्रेणी की वारिस अपीलान्त की माता स्व० श्रीमती ग्यारसी देवी एवं अपीलान्त थी। चूंकि अपीलान्त की माता का भी देहान्त हो चुका है इसलिए अपीलान्त ही स्व० नारायण की जायन्दा पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस है एवं नारायण की एक मात्र उत्तराधिकारी है। इसलिए उक्त आराजी में अपना हक व हिस्सा नियत है। इसलिए उक्त अपील आदेश निरस्त योग्य हैं।

9 यह कि अपीलाधीन ओदेश गैर कानूनी तरीके से मात्र मौखिक आधार पर स्वीकृत किये जाने के कारण एक शून्य आदेश है जिसको निरस्त किया जाना कानूनन न्यायहित में अति आवश्यक है।

10 यह कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्त को अपनी माता स्व० श्रीमती ग्यारसीदेवी का निधन हाने पर अपने नामान्तकरण खुलवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह बनवाकर पटवारी हन्का के सम्पर्क करने पर एवं उक्त नामान्तकरण की पकल दिनांक 16.07.2015 को प्राप्त होने पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
दूढ़

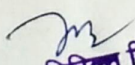
ने फर्जी तरीके से नामान्तकरण खुलवा लिया। उसके बाद रुपये पैसे का इंतजाम कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। जिसके लिए अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.01.1992 नामान्तकरण संख्या 353 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण स्वीकृत किया जावे।

रेस्पोंडेन्ट को नोटिस भेजकर तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की और से जवाब पेश किया गया।

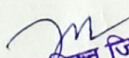
1 यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है। वह स्वीकार नहीं है।

2 यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 जिस प्रकार से वर्णित किया है व कतई स्वीकार नहीं है। बल्कि सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि नारायण पुत्र रामनाथ ने उत्तरदाता को अपने जीवनकाल में ही बाल्य अवस्था में गोद लेकर बतौर दत्तक पुत्र ग्रहण कर लिया था और उत्तरदाता ने अपने दत्तक पिता की सेवा सुश्रुषा की है। प्रार्थीया का यह कथन आराजी जैर कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक भूमि रही है। सही नहीं है। बल्कि सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि स्व० श्री नारायण के कोई पुत्री नहीं थी। क्योंकि नारायण की बेवी ग्यारसी देवी ने नामान्तकरण संख्या 279 दिनांक 11.01.1983 को नामान्तकरण की पुस्त पर स्वयं का अंगूठा निशानी दर्ज की है जिस पर हन्का पटवारी की स्पष्ट रिपोर्ट है कि नारायण फौत हो गया है। इसकी औरत ग्यारसी देवी ने जाहिर किया कि मेरे एक गोद का भोजका किशना है। अतः मेरे और लडके के नाम नामान्तकरण खोला जावे। एक्ट रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्यारसीदेवी ने भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से नामान्तकरण की पुस्त परा अपनी अंगूठा निशानी दर्ज क तथ्य अंकित किये है कि ग्यारसी देवी व नारायण के एक मात्र दत्तक पुत्र किशना ही है और इसी कारण से पटवारी हन्का की रिपोर्ट एवं गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर नारायण पुत्र रामनाथ की फौतगी पर उसके विधिक वारिसान मु० ग्यारसीदेवी बेवा नारायण वच किशना दत्तकपुत्र नारायण के नाम खाता खोला गया। प्रार्थीया ने बराय बदनियती से उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है। और विधि विरुद्ध तरीके से अपने आपको नारायण की पुत्री बताते हुऐ उक्त अपील एवं स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त नामान्तकरण वर्ष 1983में मजमे आम मे खोला गया था । जिसकी जानकारी उत्तरदाता की माता ग्यारसीदेवी को बखूबी रही है। अगर अपीलान्ट नारायण की पुत्री होती तो किसी न किसी रूप से उसे उक्त तथ्य की जानकारी अवश्य ही होती । क्योंकि लादीदेवी स्वयं अपनी उम्र 59 वर्ष अंकित है। लादी देवी दानी की ढाणी तामडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर में रहती है। और एक्ट पता अपीलान्ट को यह तथ्य कतई स्वीकारोति योग्य नहीं है कि अपीलान्ट स्व० श्री नारायण की पुत्री है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही पोषणीय नहीं होने के कारण काबिले खारिज योग्य है।

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
दूदू

3 यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है। वह स्वीकार नहीं है। बल्कि सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि मृतक नारायण पुत्र रामनाथ का उत्तरदाता गोद पुत्र है और जिस बाबत वर्ष 2014 की निर्वाचन नामावली के क्रम संख्या 189 पर उत्तरदाता किशना पुत्र नारायण का नाम अंकित है तथा परिवार राशन कार्ड 00205 में भी किशनलाल बैरवा पुत्र नारायण का नाम अंकित है तथा ग्राम पंचायत डीडावता द्वारा वर्ष 2006 से 2010 का परिवार राशनकार्ड जारी किया गया जिसमें किशनलाल बैरवा पुत्र नारायण बैरवा नाम अंकित है तथा भूमि की जोत की विशिष्टियां हेतु जारी पासबुक राजस्व बंदोबस्त की काल अवधि संवत् 2011 से 2030 में भी किशना पि0मु0 नारायण दर्ज एवं अंकित है। तथा परिवार राशन कार्ड संख्या 228 में भी किशनलाल पुत्र नारायण दर्ज व अंकित है तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जारी द्वारा विद्युत बिल खाता संख्या 16040854 पर किशनलाल पुत्र नारायण नाम दर्ज एवं अंकित है। उक्त समस्त दस्तावेजों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक जांच क रनाम अंकित किये गये है इन तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तरदाता स्व0 श्री नारायण का दत्तक पुत्र है तो उत्तरदाता के नाम खुले नामान्तरण में कोई कानूनी अवैधता नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने आप में नारायण की पुत्री होना बताकर जो दस्तावेज पंचायत द्वारा जारी कुर्सीनामा प्रस्तुत किया गया है। वह कतई सही नहीं है। क्योंकि उक्त पंचायत द्वारा न तो उक्त कुर्सीनामा जारी करते समय उत्तरदाता को कोई सूचना दी और न ही कौरम में उक्त कुर्सीनामा जारी किया गया। महज वर्तमान संरपंच को अपने प्रभाव में लेकर अपीलान्ट व उसके साथ लगे भू माफिया लोगो द्वारा उक्त दस्तावेज अब तैयार किया गया है जिसकी कोई कानूनी महत्वता नहीं है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दूसरा दस्तावेज परिवार के मुखिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र है। जिस पर ना तो सरपंच की रिपोर्ट पूर्ण रूप से अंकित है ना ही विकास अधिकारी की रिपोर्ट पूर्ण रूप से अंकित है। अर्थात् उक्त दस्तावेज अपने आप में ही अपूर्ण है। जिसके आधार पर अपीलान्ट नारायण की कतई कोई वारिस साबित नहीं होती है। इसलिए अपीलान्ट का यह तथ्य अंकित करना कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नारायण की वारिस है कतई स्वीकार योग्य नहीं है।

4 यह कि प्रार्थना पत्र का मद संख्या 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है कतई स्वीकार नहीं है। उत्तरदाता को अपने हिस्से की भूमि का पूर्ण रूप से उपयोग व उपभोग करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। तथा जवाब के अतिरिक्त कथन में रेस्पोंडेन्ट ने कहा की अपीलान्ट के समक्ष भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत की है तथा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार से अधिनियम का अंकन नहीं किया गया है। सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 81 के तहत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें क्रियान्विति स्थगित करने की अधिकारिता मात्र होती है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का अनुतोष चाहा गया है भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत

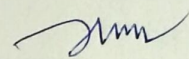
  
अतिरिक्त जिला क्लर्क  
द्वारा

अपील मे प्रदत्त नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन कानून चलने योग्य नही होने के कारण काबिले खारिज योग्य है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज की जाने की प्रार्थना की गयी हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना। तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को हम स्वीकार करना उचित समझते है। अतः आदेश है कि नामान्तकरण 279 निर्णय दिनांक 11.01.1983 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार फागी नामान्तकरण दिनांक 11.01.1983 से पूर्व की स्थिति बहाल करे। पत्रावली तहसीलदार फागी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है। उभय पक्षों को पुनः सुना जाकर गुणावगुण आधार पर पत्रावली का निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दखिल दफ्तर हो।



  
राजेन्द्रसिंह शेखावत  
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं  
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट दूरा  
दूरा (जयपुर)  
जिला जयपुर राज0